# तेजी से पैर पसार रहा है तालिबान

## मुल्ला उमर ने हाल ही में वजिरिस्तान के तालिबान नेताओं को खत लिखकर आदेश दिया कि पाकिस्तानी सेना पर हमले बंद किए जाएं, क्योंकि मुसलमानों के साथ लड़ाई जेहाद नहीं है।

**तुफैल अहमद**

पाकिस्तानी सेना का सहयोग केवल पाकिस्तानी तालिबान से नहीं, पूरे तालिबान से है। वह अफगानिस्तानी तालिबान से भी सहयोग करती है। यह पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तान में तालिबान के नेता मुल्ला उमर के बीच हाल ही में हुई बातचीत से स्पष्ट है। पाकिस्तान के तीन तालिबान गुटों ने 2009 के शुरू में शूरा इत्तेहाद मुजाहिदीन नाम से पाकिस्तान की तीन हस्तियों बैतुल्लाह मेहसूद, मौलवी नाजिर और मौलवी हाफिज गुल बहादुर की कमान में तहरीक-ए-तालिबान गठित किया है। बाद के दोनों सरकार समर्थक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गठन के बाद इस संगठन ने मुल्ला उमर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। 'हम मुल्ला उमर को अपना अमीर-उल-मुमिनीन मानते हैं।'

राजनीतिक विश्लेषकों की इस राय का इससे खंडन होता है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में तालिबान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मुल्ला उमर ने हाल ही में वजिरिस्तान के तालिबान नेताओं को खत लिखकर आदेश दिया कि पाकिस्तानी सेना पर हमले बंद किए जाएं क्योंकि मुसलमानों के साथ लड़ाई जेहाद नहीं माना जाता। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना पर हमले से तालिबान आंदोलन को नुकसान हो रहा है और अगर तालिबान लड़ाके जेहाद करना चाहते हैं तो उन्हें अफगानिस्तान आना चाहिए। एक अफगानी वेब साइट ने खबर दी है कि सच्चाई यह है कि तालिबान और उसके समर्थक यानी पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपने बलों का पुनर्गठन किया है और अफगानिस्तान में हमले तेज कर रहे हैं।

मुल्ला उमर और तालिबान से पाकिस्तान में बातचीत तालिबान-पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में अंतर को मिटा देता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मुल्ला उमर की अगुवाई में एक ही आंदोलन का गठन किया गया है- जो आजकल पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग का इच्छुक है।

इस समय पाकिस्तान-तालिबान गठबंधन को अमेरिका में ओबामा प्रशासन के आगमन और पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र में सामरिक स्थिति में बदलाव से जोड़ा जा सकता है। यह मानकर कि ओबामा के आने का मतलब है कि तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिकी अभियान तेज होगा। इसी के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपनी सामरिक नीति में बदलाव करते हुए तालिबान को अपने पक्ष में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वह अमेरिकी सेना के खिलाफ छद्म युद्ध में करेगा।

भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान-तालिबान गठबंधन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने तालिबान को आतंकवादी संगठन और समझौते को सभ्य समाज के लिए खतरनाक कहा है। विदेश राज्यमंत्री आनंद शर्मा ने चेतावनी दी है कि स्वात घाटी में अमन के लिए शरिया समझौता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुल्तान अहमद बाहीन और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ वाहिद माज्दा ने इस समझौते को क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बताया और अफगानी दैनिक काबुल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि समझौते के बाद पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में नए खतरों का सबब बनेगा। अफगानी शिया पार्टी के साप्ताहिक इक्तेदार-ए-मिल्ली में एक लेख में कहा गया है कि 'अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा खतरा महसूस किए जाने का आधार हमारे पिछले अनुभवों के कारण है। पिछले सात वर्षों से वैसे तो पाकिस्तान सरकारी तौर पर आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के संघर्ष का समर्थन करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट, अमैत्रीपूर्ण और तालिबान समर्थक रही है। जब भी पाकिस्तान में कोई घरेलू संकट आता है तो पाकिस्तान अपनी समस्याएं अफगानिस्तान पर टालने की कोशिश करता है।' अफगानिस्तान के कोनार प्रांत के गवर्नर फजलुल्लाह वाहिदी ने चेतावनी दी है कि बाजोर में युद्ध विराम से अफगानिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जहां पश्चिमी देशों की सेनाएं तालिबान से संघर्ष कर रही हैं।

(यह लेख स्वात घटनाक्रम से पहले लिखा गया था। लेकिन अब स्थिति बिलक़ुल बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने स्वात-समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि प्रस्ताव पारित करने से पहले संसद को विश्वास में लिया गया था। इस प्रस्ताव के विरोध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वाक आउट किया। आवामी नेशनल पार्टी ने भी इसका विरोध किया।

पाकिस्तान की स्वात घाटी से सटे बुनेर जिले पर कब्जा करने के बाद तालिबानी आतंकवादियों ने युवाओं को लुभाने के लिए इलाके की मज्जिदों को भर्ती केंद्र के रूप में इस्तमाल करना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक जिले की सभी मज्जिदों को भर्ती केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, ताकि मलकंड डिवीजन सहित पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके।)

(लेखकः **मेमरी के उर्दू-पश्तू मीडिया प्रोजेक्ट के निदेशक हैं।**)

> पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट, अमैत्रीपूर्ण और तालिबान समर्थक रही है। जब भी पाकिस्तान में कोई घरेलू संकट आता है तो पाकिस्तान अपनी समस्याएं अफगानिस्तान पर टालने की कोशिश करता है।'

# तालिबान के शिकंजे में पाकिस्तान

## तालिबान को स्वात-मलकंड क्षेत्र में शरिया कानून लागू करने की आजादी तो है लेकिन वहां शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आंदोलन पर नहीं है।

**तुफैल अहमद**

पाकिस्तान के अधिकारियों ने 5 मार्च, 2009 को तालिबान के साथ दूसरा समझौता किया। इससे तालिबान को क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन को नियमित करने के लिए और अधिकतर मिल गए। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल है:

अश्लीलता और फूहड़ता समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, अश्लील सीडी बेचने वाली दुकानें बंद कर दी जाएंगी, नमाज के समय दुकानें और बजार बंद रहेंगे, बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जेलों और जेल सुधारों में कुरान पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी।

तालिबान को और छूट देते हुए पाकिस्तानी सेना ने मौलाना फजलुल्लाह के मुख्यालय को खाली कर उसे सूफी मुहम्मद को सौंप दिया। पशिमोत्तर सीमा प्रांत की सरकार ने इमाम देहरी मदरसा में सुधार कर उसे काहिरा के अल-अजहर के समान महत्त्वपूर्ण इस्लामी विश्वविद्यालय बनाने का जिम्मा लिया। इसमें एक अरब रुपए की लागत आएगी और सूफी मुहम्मद उसके चांसलर होंगे। यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि इसके पाठ्यक्रम आदि के निर्धारण में पाकिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि यह समझौता केवल पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही सीमित नहीं है। बाजौर एजेंसी में तालिबान ने 23 फरवरी 2009 को सरकारी फौजो के साथ संघर्ष में एकतरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया।

एक तरह से 16 फरवरी और 5 मार्च के समझौते एकतरफा हैं। इनसे तालिबान को स्वात-मलकंड क्षेत्र में शरिया कानून करने की आजादी तो है लेकिन वहां शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आंदोलन पर नहीं है। तालिबान ने 16 फरवरी के समझौते के बदले केवल जुबानी आश्वासन दिया है कि तालिबान लड़ाके एक सप्ताह के भीतर निरस्त्र कर दिए जाएंगे।

वास्तविकता यहा है कि पाकिस्तानी सेना तालिबानी मांग के अनुसार अपनी चौकियां हटा रही है लेकिन सरकारी फौजों के खिलाफ तालिबानियों की हिंसक गतिविधियां जारी हैं। समझौते के कुछ दिन बाद ही 22 फरवरी, 2009 को तालिबान ने एक शीर्ष अधिकारी और उसके छह अंगरक्षकों का अपहरण कर लिया लेकिन दो तालिबानी बंदियों की रिहाई के बदले उन्हें छोड़ा दिया गया।

तालिबान ने 3 मार्च को स्वात में दो पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को रसद पहुंचाने वाले काफिलों पर भी तालिबानी हमले जारी हैं। प्रांतीय सरकार तालिबानी उग्रवादियों से हथियार कंधे पर लटकाकर न घूमने का केवल आग्रह कर रही है। वह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

तालिबानी हिंसा को जायज ठहराते हुए मौलाना फजलुल्लाह ने कहा; हमने शरिया लागू करने के लिए हथियार उठाया है। लोकतंत्र केवल नास्तिकों की व्यवस्था है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच लंबे समय के सामरिक गठबंधन के चलते ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान के आगे घुटने टेके। इससे तालिबानी को यह फायदा होगा कि वह पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में शरिया लागू करने और अपना नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगा। जेल से रिहा होने के बाद सूफी मुहम्मद ने ऐलान किया कि स्वात-मलकंड क्षेत्र में शरिया लागू करने के बाद पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा।

उन्होंने 23 मार्च, 2009 को अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर लोग मेरी मदद करें तो मैं देश (पाकिस्तान) के हर हिस्से में शरिया लागू करने के लिए काम करूंगा। वास्तव में पाकिस्तान के कुछ अधिकारी भी तालिबान के लक्ष्य से इत्तफाक करते हैं। सीनेट के चेयरमैन मिया रजा रब्बानी ने 24 फरवरी, 2009 को प्रस्ताव किया कि अफगान सीमा से लगे संघ प्रशासित कबीलाई क्षेत्रों (फाटा) में शरिया कानून लागू किए जाए।

अफगानिस्तान में अपना दबदबा कायम करने और पश्चिमी देशों सहित भारत जैसे विरोधियों के साथ टकराव में पाकिस्तान तालिबान और अन्य जेहादी संगठनों का अपना सहयोगी समझता है। दोनों में सहयोग का एक नमूना है स्वात घाटी में भारतीय एजेंटों के खिलाफ सरकार और तालिबान का संयुक्त अभियान।

दैनिक रोजनामा जंग ने 17 फरवरी 2009 को खबर प्रकाशित की कि 'पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का प्रशासन और मौलाना सूफी मुहम्मद भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े तत्त्वों और अपराधियों का जिले से सफाया करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। घाटी में कानून और व्यवस्था बिगाड़ने मे इन तत्त्वों का हाथ होने के बारे में सरकार के पास ठोस सबूत हैं।'

(लेखकः **मेमरी के उर्दू-पश्तू मीडिया**

> पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच लंबे समय के गठबंधन के चलते ही पाक अधिकारियों ने उसके आगे घुटने टेके। इससे तालिबान अन्य क्षेत्रों में शरिया लागू करने का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होगा।